

केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल

साइबर बाइट



डिजिटल अरेस्ट से खुद को
कैसे बचाएं?

CERT-In ने कई कमजोरियों
की पहचान की है

CERT-In ने कहा कि साइबर हमलावर दुर्भावनापूर्ण
एप्लिकेशन या वेबसाइटों के माध्यम से इन
कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं।

1. साइबर गिक्स न्यूज

ए) भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) ने एंड्रॉइड फोन में कई कमजोरियों की पहचान की है।



एंड्रॉइड वर्जन 15, 14, 13, 12 और 12L (फोल्डेबल फोन के लिए) वाले फोन का हैकर्स द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। एंड्रॉइड और गूगल क्रोम

दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए ये चिंताएं संभावित रूप से लाखों डिवाइस को जोखिम में डाल सकती हैं। "उच्च जोखिम" के रूप में रेटेड, CERT-In ने कहा कि साइबर हमलावर कोड निष्पादित करने और सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एप्लिकेशन या दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों के माध्यम से इन कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं।

CERT-In ने उपयोगकर्ताओं को सलाह दी है कि वे अपने एंड्रॉइड डिवाइस को गूगल और क्रोम द्वारा जारी किए जाने के तुरंत बाद अपडेट कर लें।

उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ब्राउज़र का नवीनतम संस्करण चला रहे हैं। गूगल ने पहले ही इस समस्या को स्वीकार किया है और इनकी पहचान कर कमजोरियों के लिए सुरक्षा पैच जारी कर दिए हैं, Windows और Mac के लिए 129.0.6668.100 और Linux के लिए 129.0.6668.89 है।

बी) डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के आसपास साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रेजरपे गृह मंत्रालय में शामिल हुआ ।

फिनटेक प्रमुख रेजरपे ने कहा कि उसने देश में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के आसपास साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य व्यवसाय और अंतिम - ग्राहकों को खुद की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी से सशक्त बनाना है, साथ ही देश भर में साइबर सुरक्षा के बारे में व्यापक जागरूकता प्रसारित करना है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के वर्तमान आंकड़ों से पता चला है कि पूरे भारत में डिजिटल धोखाधड़ी की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें प्रतिदिन 7,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की जाती हैं

I4C की रणनीतिक पहल,



चिंताजनक बात यह है कि 85 प्रतिशत साइबर शिकायतें वित्तीय

धोखाधड़ी से जुड़ी हैं, जो ऑनलाइन लेनदेन की बढ़ती भेदता को दर्शाता है। जनवरी से अप्रैल तक, पीड़ितों ने साइबर अपराधों में \$21.2 मिलियन से अधिक का नुकसान उठाया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय के निदेशक ने कहा, कि "रेजर पे के साथ यह साझेदारी रेजर पे के तकनीकी दृष्टिकोण को I4C की रणनीतिक पहलों के साथ जोड़कर हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है।"

रेजर पे अपनी चल रही पहलों के अलावा, साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्यवसायों और उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगा। फिनटेक प्लेटफॉर्म ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,600 से अधिक साइबर अपराध स्टेशनों के साथ जुड़कर निर्बाध संचालन को सक्षम बनाया है।

2. साइबर धोखाधड़ी

(ए) एनआईए ने मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी जांच में छह राज्यों में 22 स्थानों पर छापे मारे

मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को छह राज्यों में 22 स्थानों पर गहन छापेमारी की। इस अभियान का लक्ष्य एक बड़े पैमाने पर तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ना



था जो युवा भारतीयों को अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों के नाम पर

दक्षिण पूर्व एशिया के देश खासकर कंबोडिया में ले जाना शामिल था ।

छापेमारी 17 संदिग्धों के ठिकानों पर केंद्रित थी, जिनमें नवी मुंबई के वाशी और घनसोली के परिसरों के अलावा महाराष्ट्र के कई जिले शामिल थे। महाराष्ट्र के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में भी छापेमारी की गई।

एनआईए की जांच उन व्यक्तियों पर केंद्रित है जिन पर कंबोडिया और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भारतीय युवाओं की तस्करी में मदद करने का आरोप है। कंबोडिया में स्थित भारतीय एजेंटों के उप-एजेंटों, सहयोगियों और रिश्तेदारों सहित संदिग्धों की तलाशी ली गई, जो कथित तौर पर तस्करी नेटवर्क के रसद और वित्तीय लेनदेन का प्रबंधन कर रहे हैं।

छापेमारी के दौरान एनआईए अधिकारियों ने मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और मेमोरी कार्ड समेत कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। एजेंसी ने संदिग्धों के ठिकानों से कुल रूपये 34,80,800 (रूपये चौंतीस लाख अस्सी हजार आठ सौ) भी नकद बरामद किए। जांच आगे बढ़ने पर कई लोगों को आगे की पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

(बी) साइबर जालसाजों ने डॉक्टर बनकर ओडिशा में गर्भवती महिलाओं से पैसे लूटे

साइबर धोखाधड़ी की एक परेशान करने वाली और चौंकाने वाली घटना में, कई गर्भवती महिलाएं एक नए ऑनलाइन घोटाले का शिकार हो गईं, जिसमें डॉक्टर और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वालों ने उनसे रूपये ठग/लूट लिए।

साइबर अपराधी खुद को डॉक्टर और महिला एवं बाल विकास विभाग का अधिकारी बताकर गर्भवती माताओं/महिलाओं से 'ममता योजना' के तहत मिलने वाले रूपये ठग रहे हैं। यह मामला तब सामने आया जब एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और गर्भवती माता ने गजपति जिले के मोहना पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई ।

सूत्रों के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को एक जालसाज ने फोन किया, जिसने खुद को डॉक्टर और महिला एवं बाल विकास विभाग का सदस्य बताया। उसने ममता योजना के तहत राशि पाने वाली सभी गर्भवती महिलाओं के बारे में पूछताछ की और उनके फोन नंबर मांगे।

3. महीने की टिप

(ए) डिजिटल गिरफ्तारी से खुद को कैसे बचाएं



- 1. जानकारी को सत्यापित करें :** कभी भी किसी के साथ फोन या ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी या वित्तीय विवरण साझा न करें, जब तक कि आप उनकी पहचान और उनके अनुरोध की वैधता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त न हों।
- 2. अपरिचित नंबरों से सावधान रहें :** अज्ञात नंबरों से आने वाली कॉल का उत्तर देने से बचें, विशेषकर उन नंबरों से जिनका क्षेत्र कोड विदेशी हो।

जानकारी की दोबारा जांच करें: यदि आपको कोई संदिग्ध कॉल या संदेश प्राप्त होता है, तो उस जानकारी को किसी विश्वसनीय स्रोत, जैसे कि किसी सरकारी वेबसाइट या किसी ज्ञात कानून प्रवर्तन एजेंसी से सत्यापित करने का प्रयास करें

घोटाले की रिपोर्ट करें : अगर आपको लगता है कि आप डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले का शिकार हुए हैं, तो स्थानीय पुलिस या साइबर अपराध अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट/शिकायत करें। आप अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता या मोबाइल धारक /वाहक को भी इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं।

(बी) प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध, एआई प्रौद्योगिकी से उत्पन्न खतरों पर चिंता व्यक्त की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर



अपराध और एआई प्रौद्योगिकी के कारण उत्पन्न संभावित खतरों, विशेष रूप से सामाजिक और पारिवारिक

संबंधों को बाधित करने के लिए गहरी जालसाजी की क्षमता पर चिंता व्यक्त की है।

पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पुलिस कांस्टेबलों के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया और सुझाव दिया कि पुलिस स्टेशनों/थानों को संसाधन आवंटन का केन्द्र बिन्दु बनाया जाना चाहिए।

बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर उभरती सुरक्षा चिंताओं , शहरी पुलिस व्यवस्था के रुझानों और दुर्भावनापूर्ण बयानों का मुकाबला करने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया । आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर अपराध, आर्थिक सुरक्षा, आव्रजन, तटीय सुरक्षा और मादक/नार्को-तस्करी सहित राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मौजूदा और उभरती चुनौतियों पर गहन चर्चा की गई। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा चुनौतियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर व्यापक चर्चा हुई तथा सम्मेलन के दौरान उभरी जवाबी रणनीतियों पर संतोष व्यक्त किया गया।

